प्रारम्भ नहीं की जाती तो कालांतर में इलाहाबाद महानगर के आवागमन की समस्या बहुत ही जटिल हो जाएगी। जी०टी०रोड के नगर के मध्य से गुजरने के कारण वैसे ही इलाहाबाद पर आवागमन का बड़ा दबाव है।

अतएव मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर आवश्यकतानुसार प्रांतीय सरकार से विचार-विमर्श करके इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी पर नए पुलों के निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

(viii) Need for putting up a T.V. Relay Station at Pilibhit, U.P.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, पीलीभीत नगर व जिले में दूरदर्शन के चित्र या तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते अथवा दिखाई भी देते हैं तो बिल्कुल धुंधले। पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा जिला है। दूरदर्शन का लाभ उठाने में भी यह पिछड़ा है। केन्द्रीय सरकार ने टी०वी० विस्तार का जो कार्यक्रम बनाया उससे भी पीलीभीत को कोई लाभ नहीं पहुंचा। अभी धुंधले चित्र दिखाई देने की शिकायत पर बरेली व शाहजहांपुर में दूरदर्शन केन्द्र खोले गये परन्तु उनसे भी पीलीभीत को कोई लाभ नहीं पहुंचा। बरेली के दूरदर्शन केन्द्र की परिधि केवल 25-30 किलोमीटर की है जबकि पीलीभीत बरेली से 55 किलोमीटर है, यदि बरेली के दूरदर्शन केन्द्र की परिधि 30-40 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो पीलीभीत में दूरदर्शन का लाभ पहुंच सकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पीलीभीत में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करे जिससे वहां की जनता को इसके कार्यक्रमों का लाभ मिल सके अथवा बरेली के दूरदर्शन केन्द्र को इतना सशक्त करे कि उससे पीलीभीत लाभान्वित हो सके।

(ix) Need for providing the freedom fighters with more amenities

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष-महोदय, देश के एक लाख सत्ताइस हजार से अधिक स्वतन्त्रता सेनानी स्वतन्त्रता-सैनिक सम्मान पेंशन का उपभोग कर रहे हैं। प्रत्येक को तीन सौ रुपये और विधवाओं को दो सौ रुपये माहवारी की दर से पेंशन की राशि दी जा रही है। यह रकम आज की छलांग मारती हुई महंगाई को देखते हुए कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से सरकार ने स्वतन्त्रता-सेनानियों के लिए "भारत दर्शन" के वास्ते कार्ड पास छह महीने के लिए जारी करने का निर्णय लिया था। करीब बीस हज़ार लोगों को ही पास मिल पाए थे कि, सरकार ने उसे बन्द कर दिया।

स्वतन्त्रता-सेनानियों की कुछ और समस्याएं भी हैं जिनकी पूर्ति की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अतः प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वे इसी सत्र में स्वतन्त्रता-सेनानियों को निम्न सुविधाएं देने की घोषणा कर उन्हें अपनी बुढ़ापे की अवस्था निश्चिंत होकर व्यतीत करने का अवसर प्रदान करें।

1. सेनानियों को मिल रही पेंशन की राशि को तीन सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये माहवारी कर दिया जाये,

2. सेनानियों की विधवाओं को भी पांच सौ रुपये माहवारी कर दिया जाए,

3. सेनानियों को सरकारी अस्पतालों से चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाये,

4. भारत दर्शन के लिए प्रत्येक सेनानी को रेल मंत्रालय के निर्णयानुसार छह माह के लिए ए० सी० टू टायर समेत प्रथम श्रेणी के दो रेल पास यथाशीघ्र दिए जाएं,

5. तेलंगाना, पुनप्रा, वायलार, पांडिचेरी तथा दूसरे आंदोलनों में भाग लेने वाले सेनानियों को भी पेंशन की राशि दी जाए,

6. गांधी-इर्विन समझौते के बाद जेल से छुटने वाले सभी सेनानियों को पेंशन की सुविधा दी जाए।